बोर्ड परीक्षा फिर समाप्त

डॉ. सुशील जोशी

म.प्र. शासन ने निर्णय लिया है कि पांचवी में आयोजित होने वाली ज़िला स्तरीय बोर्ड परीक्षा अब नहीं होगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है। किन्तु इसमें दो अड़चनें हैं। यहां हम इन्हीं अड़चनों पर चर्चा करेंगे।

पहली अड़चन यह है कि बोर्ड परीक्षा को खत्म करने का जो कारण बताया गया है वह परेशान करने वाला है। मूलतः यह कहा गया है कि पांचवीं बोर्ड परीक्षा के कारण उत्पन्न तनाव के चलते बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। दैनिक भास्कर (10 अक्टूबर 2007) में प्रकाशित समाचार के मुताबिक प्रदेश में हर साल बोर्ड परीक्षा के भय से दो लाख बच्चे चौथी कक्षा के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इस वक्तव्य में दो अलग-अलग असम्बंधित बातों को जोड़कर रख दिया गया है। पहली बात है कि दो लाख बच्चे चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। हम इस बात की सत्यता पर तो विचार करेंगे ही। और यदि यह बात सत्य भी है, तो यह कहने का क्या आधार है कि ये बच्चे परीक्षा के भय से स्कूल छोड़ते हैं? दूसरी बात, कहा जा रहा है कि इस 'बोर्ड' का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है।

शाला त्याग

यह आम धारणा है कि पहली कक्षा में जितने बच्चे भर्ती होते हैं, उनमें से काफी सारे बच्चे पांचवीं तक नहीं पहुंचते। इसे प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना के लिए पहली कक्षा की दर्ज संख्या और पांचवीं कक्षा की दर्ज संख्या का अनुपात निकाला जाता है। कई अध्ययन व सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यह दर काफी अधिक है, बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ते हैं।

मगर ऊषा जयचंद्रन द्वारा किए गए एक ताज़ा अध्ययन में इस धारणा और गणना की इस विधि पर

सवाल उठाया गया है। *इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली* के 17 मार्च 2007 के अंक में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है दरअसल पहली कक्षा की दर्ज संख्या कई कारणों से बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाई जाती है। अर्थात पहली कक्षा के हाज़िरी रजिस्टर में दर्ज बच्चे वास्तव में स्कूल में कभी दाखिल हुए ही नहीं थे।

जयचंद्रन ने शाला त्याग के परिमाण की गणना के लिए एक अलग तरीका अपनाया। नेशनल सैम्पल सर्वे से उन्होंने यह पता किया कि 15-19 वर्ष समूह में कितने बच्चे हैं जो कभी-न-कभी स्कूल में दाखिल हुए थे। यह आंकड़ा सैम्पल सर्वे के 52वें चक्र में दर्ज किया गया था। फिर उन्होंने यह पता किया इनमें से कितने बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की।

इस तरह से गणना करने पर शाला त्याग की दर काफी कम निकलती है। उदाहरण के लिए 1997-98 के लिए शाला त्याग का सरकारी आंकड़ा 26 प्रतिशत बताया गया है । जबकि जयचंद्रन के तरीके से शाला त्याग की दर ग्रामीण क्षेत्रों में 6.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में मात्र 4.4 प्रतिशत आती है। सैम्पल सर्वे में स्कूल में दाखिल होने का आंकड़ा परिवारों से प्राप्त किया जाता है जबकि सरकारी गणना का आधार स्कूल का हाज़िरी रजिस्टर या

दाखिल खारिज रजिस्टर होता है। उपरोक्त चर्चा से लगता है कि शाला त्याग उतनी बड़ी समस्या नहीं है। मुख्य समस्या तो यह है कि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल में दाखिल ही नहीं होते हैं।

शाला त्याग के कारण (प्रतिशत में)

	ग्रामीण	शहरी
1. पढ़ाई में बच्चे की रुचि न होना	37.2	37.4
2. पढ़ाई में पालकों की रुचि न होना	12.5	8.8
3. स्कूली पढ़ाई से जूझने में असमर्थता	16.4	13.7
4. मज़दूरी करना	2.5	4.6
5. अन्य आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी	6.1	5.3
6. घरेलू कामकाज	3.7	3.9
7. वित्तीय अड़चनें	11.2	15.8
8. अन्य	7.9	7.4

शाला त्याग के कारण

बहरहाल, जितने भी बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, तो क्यों छोड़ते हैं। आम धारणा यह है कि आर्थिक तंगी के कारण गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के काम में मदद देने के लिए, मज़दूरी करने के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। अब म.प्र. शासन बता रहा है कि परीक्षा का डर शाला त्याग का एक प्रमुख कारण है। सवाल यह है कि ये बातें हम किस आधार पर कह रहे हैं।

जयचंद्रन ने इस बात पर भी नेशनल सैम्पल सर्वे के आंकड़ों की मदद ली है। बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण काफी अलग हैं, यह बात तालिका से साफ नज़र आती है। यह तालिका सैम्पल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर जयचंद्रन ने तैयार की है।

तालिका से स्पष्ट है कि स्कूल छोड़ने की प्रमुख वजह बच्चे में रुचि का अभाव है। स्कूली शिक्षा से न जूझ पाना और वित्तीय अड़चनें दूसरे नंबर पर हैं। स्कूली शिक्षा में पालकों की अरुचि तीसरे नंबर का कारण है।

पढ़ाई में रूचि न होना या पढ़ाई में मज़ा न आना, या पढ़ाई बेमानी लगना जैसे कारण कई अन्य अध्ययनों में भी सामने आए हैं। बस्ते का बोझ कम करने के लिए बनाई गई यश पाल समिति ने भी इसे एक प्रमुख मुद्दा माना था। यश पाल समिति का मत था कि स्कूलों में सबसे बड़ा बोझ अर्थहीनता का है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने शिक्षा में सुधार की बातें तो बहुत की हैं मगर उसे बच्चों के लिए सार्थक व आनंददायक अनुभव बनाने की दिशा में खास कुछ किया नहीं गया। सैम्पल सर्वे के आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि शिक्षा को बच्चों व उनके पालकों के लिए रुचिकर बनाना शायद सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होगा।

परीक्षा की भूमिका

यहां हमें इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि परीक्षा से हम क्या अपेक्षा करते हैं। बोर्ड परीक्षा के होते हुए भी हम इस समस्या से ग्रस्त रहे हैं कि कक्षा 6 में पहुंचने वाले बच्चे लिखना तो दूर, ढंग से हिंदी पढ़ भी नहीं पाते। बड़ी संख्या में बच्चे हिज्जे कर-करके पढ़ते हैं और जो पढ़ा उसे समझते नहीं हैं। गणित में उपलब्धियों की चर्चा न करना ही बेहतर होगा। ऐसा क्यों है कि पांच वर्षों की स्कूली शिक्षा (और बोर्ड परीक्षा) के बावजूद सीखने के संदर्भ में हमारी उपलब्धियां इतनी घटिया हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं मगर यहां उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यह तो ज़ाहिर है कि परीक्षा सीखने में कोई योगदान नहीं देती।

मगर सवाल यह है कि आपके पास बच्चों की प्रगति के आकलन का कोई तो तरीका होना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या यह तरीका परीक्षा ही होगा। और मुख्य सवाल तो यह है - क्या बच्चों की प्रगति के लिए ज़रूरी सुविधाएं और माहौल उपलब्ध कराया गया है? इनके अभाव में बच्चों का आकलन कितना उचित है? बोर्ड परीक्षा करने और न करने से बच्चों के सीखने पर असर नहीं पड़ता है। ***(स्रोत फीचर्स)***